बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 71 ● नई दिल्ली ● वीरवार 25 दिसम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

साफ हवा नहीं दे पा रहे तो एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी करें कम, हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछे तीखे सवाल

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर में बिगड़ते वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी। न्यायालय ने सरकार से कहा कि या तो नागरिकों को स्वच्छ हवा की उपलब्धता सुनिश्चित करे या एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी (जीएसटी) तुरंत कम करे। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के मद्देनजर जीएसटी प्रणाली के तहत उच्चतम 18फीसदी कर को कम करना न्यूनतम आवश्यक कदम बताया। यह सुनवाई अधिवक्ता कपिल मदन की याचिका के बाद हुई, जिसमें उन्होंने न्यायालय से एयर प्यूरीफायर को चिकित्सा उपकरण की श्रेणी में रखने और उन पर जीएसटी घटाकर 5फीसदी करने का आग्रह किया था।

दिल्ली-एनसीआर से कोहरा अचानक गायब! क्रिसमस के बाद बदल सकता है मिजाज; देश के कई क्षेत्रों में विजिबिलिटी रही जीरो

नई दिल्ली।

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार सुबह का मौसम पूर्वानुमानों के उलट रहा। मौसम विभाग के मुताबिक घना या कम से कम मध्यम स्तरक का कोहरा छाए रहने की उम्मीद थी, लेकिन दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सुबह का नजारा अलग दिखा। न तो शहर कोहरे की चादर में लिपटे दिखे, न ही विजिबिलिटी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। मंगलवार के मुकाबले मौसम अपेक्षाकृत बेहतर रहा। हालांकि तापमान में भी बहुत यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई। अगले 7 दिनों में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 से 20 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। यानी कोहरा भले ही फिलहाल नहीं रहा हो, लेकिन ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने वाला है।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, हवा की हल्की सक्रियता और नमी का संतुलन न बनने की वजह से कोहरा अनुमान के अनुरूप नहीं रहा। आमतौर पर जब हवा की रफ्तार बेहद कम और नमी यादा होती है, तब घना कोहरा छाता है। बुधवार को ये स्थितियां पूरी तरह नहीं बन सकीं।

क्रिसमस पर कैसा रहेगा मौसम?

25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन दिल्ली-एनसीआर में मौसम सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। 26 दिसंबर को घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है

और ठंड का असर भी बढ़ेगा।

इन राज्यों में कोहरे का कहर तय

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में कोहरा और शीतलहर परेशान कर सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर को शीत दिवस की स्थिति बनने की संभावना है, जबकि बिहार में 23 से 28 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है।

इन शहरों में रहें सतर्क

आगरा, बरेली, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद (हिंडन एयरपोर्ट), अमृतसर, हिसार, अंबाला और हिमाचल के बिलासपुर में अगले दो दिनों तक कोहरा परेशान कर सकता है।

पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 23 दिसंबर और फिर 27 से 29 दिसंबर के बीच बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 28-29 दिसंबर को झमाझम बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर, दिल्ली-एनसीआर में कोहरा फिलहाल अनुमान के बावजूद गायब है, लेकिन यह राहत अस्थायी है। क्रिसमस के बाद ठंड, कोहरा और पहाड़ी इलाकों में बारिश-बर्फबारी एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकती है।

हालांकि देश के कई इलाकों में जीरो रही विजिबिलिटी

देश के कई इलाकों में बुधवार सुबह जीरो विजिबिलिटी रही। प्रयागराज, आदमपुर, हलवारा, जम्मू और सरसावा जैसे एयरपोर्ट पर सुबह 6:30 बजे विजिबिलिटी जीरो थी। वहीं, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सुबह 7 बजे विजिबिलिटी 300 मीटर दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बुधवार सुबह घने कोहरे की चादर नजर आई। आलम ये था कि कुछ मीटर दूर तक की चीजों को देखना तक मुश्किल हो गया।

दिल्ली मेट्रो का महाविस्तार! मोदी सरकार ने 12015 करोड़ में 13 नए स्टेशनों को दी मंजूरी, बदलेगी दिल्ली की तस्वीर

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (24 दिसंबर) को दिल्ली मेट्रो परियोजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत 12,015 करोड़ रुपये है।

इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करना और यातायात की भीड़ को कम करना है। दिल्ली मेट्रो के चरण 5ए में 13 नए स्टेशन होंगे। प्रस्तावित विस्तार से 16 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनेगी जिसमें 13 स्टेशन होंगे - 10 भूमिगत और तीन एलिवेटेड। परियोजना पूरी होने पर दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर से अधिक लंबा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चरण 5ए को मंजूरी दे दी है, जिसमें 13 स्टेशन शामिल होंगे। 12,015 करोड़ रुपये की लागत से 16 किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर से अधिक लंबा हो जाएगा।

दिल्ली मेट्रो का विस्तार तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक, रामकृष्ण आश्रम से इंद्रप्रस्थ तक और एयरोसिटी से टर्मिनल 1 तक किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो के चरण 5ए परियोजना के तहत तीन नए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं आर.के. आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ (9.913 किमी), एयरोसिटी से आईजीडी एयरपोर्ट टी-1 (2.263 किमी) और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज (3.9 किमी)। इस परियोजना की कुल लंबाई 16.076 किमी है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। आरके आश्रम मार्ग-इंद्रप्रस्थ खंड बॉटनिकल गार्डन-आरके आश्रम मार्ग कॉरिडोर का विस्तार होगा। यह सेंट्रल विस्टा क्षेत्र को मेट्रो कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिसका वर्तमान में पुनर्विकास कार्य चल रहा है। एयरोसिटी-आईजीडी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद-कालिंदी कुंज खंड एयरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर का विस्तार होंगे और तुगलकाबाद, साकेत, कालिंदी कुंज आदि जैसे राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिणी भागों से हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। इन विस्तारों में 13 स्टेशन शामिल होंगे। इनमें से 10 स्टेशन भूमिगत और तीन स्टेशन एलिवेटेड होंगे। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए वैष्णव ने बताया कि विस्तार परियोजना की अवधि तीन वर्ष है। मंत्री ने आगे कहा, दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के चरण-वीए के निर्माण की समयसीमा तीन वर्ष है। निर्माण कार्य अधिकतर सुरंग खोदने वाली मशीनों का उपयोग करके भूमिगत रूप से किया जाएगा, जिससे यातायात में न्यूनतम बाधा उत्पन्न होगी।

राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया एकाधिकार को बढ़ावा देने का आरोप, बोले- सामंती मानसिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को भाजपा सरकार की उन नीतियों की आलोचना की, जिनसे उनके अनुसार छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुंचा है, खासकर वैश्य (व्यापारी) समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने वैश्य समुदाय को अपना पूरा समर्थन देते हुए इसे भाजपा की सामंती मानसिकता के खिलाफ लड़ाई बताया। उन्होंने समुदाय के संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे अर्थव्यवस्था पर सरकारी कार्यों के नकारात्मक प्रभाव की चेतावनी बताया। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि हमारा व्यवसाय पतन के कगार पर है - व्यापार जगत में वैश्य समुदाय की इस पीड़ादायक पुकार ने हमें अंदर तक झकझोर दिया है। जिस समुदाय ने ऐतिहासिक रूप से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में इतना योगदान दिया है, वह आज निराशा में है - यह खतरे की घंटी है। सरकार ने एकाधिकारों को खुली छूट दे दी है और छोटे और मध्यम व्यापारियों को नौकरशाही और गलत जीएसटी जैसी दोषपूर्ण नीतियों की जंजीरों में जकड़ दिया है।

उन्होंने भाजपा पर एकाधिकार को बढ़ावा देने और छोटे व्यापारियों पर नौकरशाही और दोषपूर्ण नीतियों, जैसे कि गलत जीएसटी, का बोझ डालने का आरोप लगाया। पोस्ट में लिखा था कि यह सिर्फ नीतिगत विफलता नहीं है - यह उत्पादन, रोजगार और भारत के भविष्य पर सीधा हमला है। यह भाजपा सरकार की सामंती मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है। और इस लड़ाई में, मैं देश के व्यापार की रीढ़ माने जाने वाले वैश्य समुदाय के साथ पूरी ताकत से खड़ा हूं। इसी बीच, राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 पर संसद में चर्चा न करने का आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक विकास लाने के लिए नहीं बल्कि विनाश लाने के लिए है, जिसकी कीमत भारतीयों को अपनी आजीविका खोकर चुकानी पड़ेगी। गांधी ने लिखा कि कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं, संसद में कोई विचार-विमर्श नहीं, राज्यों की कोई सहमति नहीं - मोदी सरकार ने एमजीएनआरईजीए और लोकतंत्र दोनों पर ही बुलडोजर चला दिया है। यह विकास नहीं, बल्कि विनाश है - जिसकी कीमत लाखों मेहनतकश भारतीयों को अपनी आजीविका खोकर चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का यह लेख अवश्य पढ़ें, जो इस गंभीर मुद्दे के हर पहलू को उजागर करता है।

चुनाव के चलते मिली जमानत, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, सेंगर को जमानत मिलने पर पीड़िता ने उठाया सवाल

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट के वर्ष 2017 के उन्नाव दुष्कर्म केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने और जमानत देने के फैसले के खिलाफ पीड़िता ने अपनी मां और महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना के साथ मंगलवार देर शाम दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। पीड़िता ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि फैसला सुनकर बुरा लगा तो वहीं जान देने का फैसला लिया लेकिन परिवार के बारे में सोचकर रुक गई। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। अगर ऐसा दुष्कर्म आरोपी बाहर आएगा, तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? सब असुरक्षित हो गए हैं। कहा- चुनाव के चलते उसे जमानत मिली है। वह अब न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के लिए बैठी पीड़िता और अन्य प्रदर्शनकारियों को कुछ देर बाद ही इंडिया गेट से हटा दिया गया था। पीड़िता ने इंडिया गेट पर कहा कि उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है, ताकि उसकी पत्नी चुनाव लड़ सके। उसकी जमानत रद्द होनी चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने के खिलाफ धरने पर बैठीं पीड़िता की मां ने कहा कि मेरा परिवार अब खतरे में है। हम देश की बहनों और बेटियों के लिए लड़ते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। उन्नाव दुष्कर्म केस के दोषी की सजा निलंबित करने पर महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने कहा कि उन्हें शुरू से ही बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। आज ऐसा क्या हो गया कि आरोपी को बेल मिल गई। दुष्कर्म के दोषी को बेल मिल रही है और बेगुनाह जेल में रखे जा रहे हैं। आज कोई उनके साथ नहीं खड़ा है।

पीड़िता की बहन ने कहा कि उसने मेरे चाचा को मारा और फिर मेरे पिता को फिर मेरी बहन के साथ यह घटना हुई और अब वह रिहा हो गया है। अगर उन्होंने उसे रिहा कर दिया है तो हमें जेल में डाल देना चाहिए। कम से कम हमारी जान वहां सुरक्षित रहेगी। मेरा एक भाई है, कौन जानता है कि वे उसके साथ क्या कर सकते हैं? उनके कई आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब जब वह वापस आ रहा है तो तुम मेरा क्या कर सकते हो? मैं तुम में से हर एक को मार डालूंगा। सजा निलंबित होने पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि यह एक नया नियम बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 500 किमी दूर हों या घर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपने अपराध किया है और आपको सज़ा मिली है। कोर्ट को पीड़ित और उसके साथ जो हुआ, उसे ध्यान में रखते हुए इस पर निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए। बिल्कुल भी बेल नहीं मिलनी चाहिए। उस परिवार को अभी भी खतरा है। कई बार ऐसा हुआ है कि निचली अदालत और हाई कोर्ट ने पीड़ित को सज़ा दी है, लेकिन फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट खुद ही मज़ाक बना रहा है कि ऐसा फैसला कैसे लिया जा सकता है। फैसले के खिलाफ पीड़िता और उसकी मां ने इंडिया गेट पर मंगलवार देर शाम को विरोध प्रदर्शन किया। साथ में महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना भी शामिल थीं। काफी मशक्कत और समझाने के बाद पुलिस ने उन्हें विरोध प्रदर्शन वाली जगह से हटाया। इसमें बाद इंडिया गेट समेत कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी।

आप को बड़ा झटका, चंडीगढ़ महापौर चुनाव से पहले दो पार्षद भाजपा में शामिल, अमित शाह से मुलाकात की संभावना

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) की दो पार्षदों ने बुधवार को चंडीगढ़ महापौर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गईं। सुमन देवी और पूनम देवी ने जनवरी में होने वाले महत्वपूर्ण चुनावों से पहले अपनी निष्ठा बदली। ऐसी अटकलें हैं कि दोनों पार्षद आज पंचकुला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकती हैं। इसे भगवा पार्टी के पक्ष में एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है, क्योंकि वह चंडीगढ़ में महापौर पद पर पुनः नियंत्रण पाने के प्रयास कर रही है। भाजपा की हरप्रीत कौर बाबला चंडीगढ़ की मौजूदा महापौर हैं। उन्होंने 19 वोट हासिल करके चुनाव जीता। क्रॉस-वोटिंग के एक उल्लेखनीय उदाहरण के बाद बाबला को आम आदमी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन से आगे निकलने में मदद मिली, जिसे केवल 17 वोट ही मिल सके। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पंचकुला में कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मौजूद हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उनके दौरे से पहले, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को उन कार्यक्रमों की अंतिम तैयारियों की समीक्षा की, जिनमें शाह को भाग लेना है। सैनी ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हों। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर घोषित कर दिया था, जिससे पिछले नतीजे पलट गए थे, जिसमें भाजपा उम्मीदवार को पहले विजेता घोषित किया गया था। यह फैसला पिछले साल 20 फरवरी को आया था। यह विवाद तब शुरू हुआ जब मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को कैमरे पर आप-कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में आठ मतपत्रों को अमान्य घोषित करते हुए देखा गया। इस कार्रवाई से शुरुआत में चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में प्रभावित हुआ था। कोर्ट के फैसले के बाद, कुलदीप कुमार को आधिकारिक तौर पर निर्वाचित मेयर के रूप में मान्यता दी गई, जिससे 2024 के चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ा विवाद समाप्त हो गया।

राव की सोच की बुनियाद पर भारत बना चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था

उमेश चतुर्वेदी ।

पामुलपार्थी वेंकट नरसिंह राव...यही पूरा नाम था उनका। आज ही के दिन ठीक इक्कीस साल पहले उन्होंने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आखिरी सांस ली थी, जिसे देश के सबसे बेहतरीन सार्वजनिक अस्पताल में माना जाता है। एम्स के नाम से विख्यात इस अस्पताल में जब उनकी आत्मा उनके शरीर रूपी पिंजरे से उड़ गई, तब देश में उन डॉक्टर मनमोहन सिंह का शासन था, जिन्हें उन्होंने ही राजनीति की दुनिया में प्रवेश कराया था। राव कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और गरिमापूर्ण विदाई के हकदार थे। लेकिन उनकी ही पार्टी ने उन्हें वह विदाई मयस्सर नहीं होने दी और देश का प्रधानमंत्री भी मौन व्रत धारण किए रह गया। नेहरू, इंदिरा और राजीव को भारत रत्न देने वाली कांग्रेस की अगुआई वाली सरकार ने अपने ही उस राव को उचित सम्मान देना उचित नहीं समझा, जिसके वे अध्यक्ष रह चुके थे। भारतीय अर्थव्यवस्था को उबार इन दिनों दुनिया देख रही है। लेकिन पिछली सदी के अस्सी के दशक में अर्थव्यवस्था बेहद खराब हालत में पहुंच चुकी थी। हालत इतने बुरे थे कि भारत को अपना रिजर्व सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। राव से ठीक पहले प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा, 'जीवन जैसा जिया' में इस गिरवी प्रकरण की पूरी जानकारी दी है। चंद्रशेखर के बाद एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बने राव के सामने तत्कालीन कैबिनेट सचिव ने भारतीय अर्थव्यवस्था की बुरी गत की जानकारी दी तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। ऐसे हालात में उनका विचलित होना स्वाभाविक था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और प्रोफेसनल अर्थशास्त्री को देश का वित्त मंत्री बनाने की सोची। उन्हें तब दो नाम सुझाए गए थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके आईजी पटेल और मनमोहन सिंह। राव की पहली पसंद पटेल थे, लेकिन उन्होंने अपनी बीमार और बुजुर्ग मां की देखभाल के चलते यह जिम्मेदारी भरा पद लेना स्वीकार नहीं किया। नियति मनमोहन सिंह के पक्ष में थी। मनमोहन वित्त मंत्री बने। 1991 की 25 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करते हुए मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को खोल दिया। आर्थिक मोर्चे पर जारी लाइसेंस राज की विदाई की शुरुआत हुई। आर्थिक खुलेपन ने देश की आर्थिकी की जो नींव रखी, आज उसी नींव पर आगे बढ़ते हुए देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था का गौरव हासिल कर चुका है। बेशक यह सब मनमोहन सिंह की बदौलत हुआ। लेकिन अगर उनकी पीठ पर नरसिंह राव का हाथ नहीं होता तो क्या वे भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक व्यवस्था के साथ कदमताल करने के लिए उद्यत हो सकते थे? निश्चित तौर पर इसका जवाब ना में है। भारत की आर्थिकी को मजबूत बुनियाद देने के साथ ही वैश्विक व्यवस्था के साथ कदमताल के लिए तैयार करने में मनमोहन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन बिना नरसिंह राव के मजबूत समर्थन के, वे ऐसे कदम नहीं उठा सकते थे। आज भारत की आर्थिकी की जो वैश्विक चमक दिख रही है, उसके असल नींव निर्माता नरसिंह राव ही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस कांग्रेस के वे नेता रहे, जिस कांग्रेस के साथ उन्होंने अपनी समूची राजनीतिक यात्रा पूरी की, उस कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया। किनारा करने की वजह रहा बाबरी विध्वंस। छह दिसंबर 1992 को बाबरी का ध्वंस हुआ। ऐसा नहीं कि नरसिंह राव ने ध्वंस को रोकने की तैयारी नहीं की थी। गांधी-नेहरू परिवार के नजदीकी रहे पूर्व विदेश सेवा अधिकारी और कांग्रेसी राजनेता मणिशंकर अय्यर राव को इसी वजह से भाजपा का पहला प्रधानमंत्री कहते हैं। बाबरी विध्वंस के बाद वामपंथी बौद्धिकों के एक खेमे ने उन्हें खाकी निकर वाला कहना शुरू कर दिया था। यहां यह बताना जरूरी है कि खाकी निकर कुछ साल पहले तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की गणवेश होती थी। लेकिन नरसिंह राव ने अपने ऊपर लगे आरोपों का पुस्तक लिखकर जवाब दिया है, जो 2004 में उनके निधन के बाद प्रकाशित हुई है। 'अयोध्या- छह दिसंबर' नामक यह पुस्तक साल 2006 में प्रकाशित हुई। इस किताब में एक तरह से राव ने बाबरी ध्वंस को लेकर उन पर लगने वाले अकर्मण्यता के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया है।

इसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन और उससे पहले की घटनाओं, अपनी कार्रवाइयों और तब के राजनीतिक दबावों को लेकर पूरी जानकारी दी है। इसमें उन्होंने बताया है कि आखिर उत्तर प्रदेश में वे संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा पाए। उन्होंने बताया है कि राज्यपाल की रिपोर्ट राष्ट्रपति शासन के पक्ष में नहीं थी और उनके सामने कई संवैधानिक चुनौतियां और बाधाएं भी थीं। इन तथ्यों के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि आखिर क्यों मस्जिद को बचाने की उनकी कोशिशें किस तरह नाकाम रहीं। विनय सीतापति ने 'हाफ लायन' नाम से राव की जीवनी लिखी है। इस पुस्तक में वे भी तमाम तथ्यों से साबित करते हैं कि राव चाहकर भी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते थे। अपनी किताब में राव ने तफसील से बताया है कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि अयोध्या पहुंच रहे कारसेवक शांतिपूर्ण हैं। राव ने साथ ही यह भी बताया है कि तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर मस्जिद की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। ऐसे में संवैधानिक मर्यादाओं और संघीय ढांचे के संवैधानिक प्रावधानों के कारण उनके हाथ बंधे हुए थे। राव ने अपनी पुस्तक में राम मंदिर आंदोलन के पीछे की राजनीतिक चालों और धार्मिक भावनाओं के दोहन के खतरों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें दो राय नहीं कि बाबरी ध्वंस के बाद कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह बदल गई। दलित, ब्राह्मण और मुसलमान की जातीय कॉम्बिनेशन के दम पर लंबे समय तक शासन में रही कांग्रेस का समर्थक आधार छीजने लगा। अल्पसंख्यकों ने कई प्रमुख राज्यों मसलन उत्तर प्रदेश, बिहार आदि से किनारा कर लिया। इसका असर कांग्रेस की सत्तावादी राजनीति पर पड़ा। जिस समय बाबरी ध्वंस हुआ, उस समय गांधी-नेहरू परिवार राजनीति से दूर था। सोनिया गांधी तो सक्रिय राजनीति में 1998 में आईं। लेकिन उनके इशारे पर कांग्रेस का एक बड़ा खेमा काम करता रहा। अर्जुन सिंह, प्रियरंजन दास मुंशी, मणिशंकर अय्यर, प्रणब मुखर्जी आदि कांग्रेसी प्रथम परिवार के इशारे पर काम करते रहे। जब 1996 में कांग्रेस संसदीय चुनावों में हार गई तो नरसिंह राव को इस खेमे ने ना सिर्फ अप्रासंगिक बनाना शुरू किया, बल्कि उन्हें महत्वहीन भी बना दिया। कांग्रेस पर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 19884 में हुए सिख विरोधी हिंसा का भी दाग है। दिलचस्प यह है कि उस वक्त राजीव सरकार के गृहमंत्री नरसिंह राव ही थे। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। क्योंकि उनके साथ राजीव गांधी का वह बयान चिपका हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंसा से ग्रस्त पंजाब को पटरी पर लाने वाले नरसिंह राव ही थे।

नरसिंह राव ने ही लुक ईस्ट नीति शुरू की और एशियाई देशों से भारत के मजबूत संबंध बनाने शुरू किए थे। लेकिन उनके इन योगदानों को भुला दिया गया। राव सिर्फ भारतीय आर्थिकी के ही शिल्पकार नहीं थे, बल्कि देश के आतंकग्रस्त इलाकों को सख्त प्रशासन और विकास कार्यों के समायोजन के जरिए मुख्यधारा में जोड़ने वाले रचनाकार भी रहे। मोदी सरकार के बारे में कहा जा सकता है कि उसने राजनीतिक कारणों से राव को 2024 में भारत रत्न दिया। लेकिन यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि राव का सम्मान भारत के बदलाव का दौर शुरू करने वाले शिल्पी का सम्मान है।

सम्पादकीय...

बांग्लादेश में कट्टरपंथ का ज्वालामुखी

बांग्लादेश में पिछले साल उठी चिंगारी अब ज्वालामुखी में बदल चुकी है। छात्र नेता और शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट में बड़ी भूमिका निभाने वाले उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंसा, आगजनी और बवाल फिर से शुरू हो गया है। हिंसा की ज्वालामुखी में अल्पसंख्यक हिन्दुओं की हत्याओं से लेकर भारत विरोधी जनभावनाओं का उग्र होना शामिल है। हिंसक भीड़ ने हिन्दू मजदूर दीप चंद्र दास की पीट-पीट कर हत्या करने के बाद शव को पेड़ से लटका कर जला दिया। इसके बाद हिंसक भीड़ ने पुलिस और सेना के सामने नाच-नाच कर जश्न मनाया। हिंसक भीड़ ने बीएनपी के नेता के घर में आग लगा दी जिसमें 7 वर्षीय बच्ची जिंदा जल गई। हिंसक भीड़ ने मोहम्मद यूनुस सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया कि वह जल्द से जल्द उस्मान हादी के हत्यारों को गिरफ्तार करे अन्यथा उन्हें भी सरकार से हटा दिया जाएगा। बीते साल अगस्त में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाये जाने के बाद से लगातार हिन्दुओं को निशाना बनाया जा रहा है और वहां अब तो हिन्दू महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए कहा जा रहा है। भारत विरोधी कट्टरपंथी ताकतें प्रभावी हो चुकी हैं। बांग्लादेश में 2 माह बाद यानि फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में हिंसा का भड़कना चुनावों को अवरुद्ध करने का कारण बन सकता है। प्रधानमंत्री की हैसियत से काम करने वाले मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और उनके साथ सरकार में शामिल नेता बार-बार भारत विरोधी भावनाओं को भड़का रहे हैं। उस्मान हादी के जनाजे में भी भारत विरोधी पोस्टर देखे गये और भारत विरोधी नारे लगे। उस्मान हादी एक कट्टरपंथी मौलाना का नेता था। अतिवादी जेहादी विचारधारा के चलते ही उसने हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करने वाले बयान दिए थे। उसकी हत्या करने वाले जानते थे कि हमले का आरोप भारत पर ही लगेगा और हुआ भी यही। कट्टरपंथी ताकतों ने उस्मान हादी की हत्या का आरोप भारत पर मढ़कर ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिससे यह निश्चित है कि बांग्लादेश के आगामी चुनाव में भारत विरोध ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। हालात बताते हैं कि अमेरिका के समर्थक माने-जाने वाले मोहम्मद यूनुस के मुंह को सत्ता का खून लग गया है और वह सरकार से हटना नहीं चाहते। वे चुनावों को किसी न किसी तरह टालना चाहते हैं। वे कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। अब कट्टरपंथियों ने भारतीय दूतावास और वीजा केन्द्रों को निशाना बनाना शुरू किया तब भी वे उदासीन बने रहे। हैरानी की बात तो यह है कि 1971 के युद्ध में भारत ने ही बांग्लादेश को आजाद कराया था। बीते 16 दिसम्बर को भारत ने विजय दिवस मनाया क्योंकि 1971 में इसी दिन पाकिस्तान के 90 हजार सैनिकों ने भारत के सामने हथियार डाल दिये थे लेकिन बांग्लादेश भारत के एहसानों को भुलाकर अब भारत के ही विरोध में खड़ा है। शेख हसीना और उनकी अवामी लीग सरकार के प्रति भारत के कथित नरम रवैये की शुरू से ही चर्चा होती रही है। बांग्लादेश के छात्र नेता और जमात-ए-इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टियां बीते साल अगस्त से ही यह मुद्दा उठाती रही हैं। बीते अगस्त से ही भारत में रह रहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण देने के मुद्दे पर संबंधों में तनातनी रही है। बांग्लादेश की एक अदालत ने हसीना को मौत की सजा सुनाई है। उसके बाद अंतरिम सरकार कम से कम दो बार औपचारिक रूप से भारत से हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग कर चुकी है लेकिन भारत ने इस पर चुप्पी साध रखी है। इससे कट्टरपंथी दलों और अंतरिम सरकार की नाराजगी लगातार बढ़ी है। अब हाल में दो तरफा बयान ने द्विपक्षीय संबंधों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पिछले एक दशक तक शेख हसीना सरकार को भारत का करीबी माना जाता। इस दौरान सीमा सुरक्षा, आतंकवाद पर सहयोग, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और चीन के प्रभाव को संतुलित करने जैसे मुद्दों पर ढाका और दिल्ली के साझेदारी मजबूत रही लेकिन हसीना के पतन के बाद एक नई राजनीतिक पीढ़ी उभरकर सामने आई है जो भारत और शेख हसीना को लेकर जो रिश्ते हैं, उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। बांग्लादेश में शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान जो चुनाव हुए उसमें काफी कम वोटर टर्नआउट रहे हैं। काफी कम संख्या में लोगों ने वोट डाले हैं। ऐसे में फरवरी 2026 में जो चुनाव होने हैं, उसे लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है। लोगों ने 17 सालों से वोट नहीं डाले हैं, इसलिए उनमें वोट डालने की जो भूख है, वो उनके चेहरे से आप महसूस कर रहे हैं। अराजकता की स्थिति में कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी को लगता है कि उनके पास सत्ता पाने का मौका है। इन ताकतों को पाकिस्तान, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तान की आईएसआई के अफसरों ने ढाका में डेरा डाल रखा है।

खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बीएनपी का प्रभाव लोगों में है लेकिन वह खुद वयोवृद्ध और अस्वस्थ है। शेख हसीना की पार्टी को चुनावों के लिए प्रतिबंधित किया जा चुका है। ऐसे में? निष्पक्ष चुनावों की उम्मीद नहीं की जा सकती। बांग्लादेश में चीन का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है। शशि थरूर के नेतृत्व वाली संसदीय समिति ने सरकार को आगाह कर दिया है कि आवामी लीग की गिरावट, युवा नेतृत्व वाले राष्ट्रवाद का उदय इस्लामी ताकतों की वापसी और साथ ही चीन और पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव यह सभी मिलकर बांग्लादेश में निर्णायक मोड़ पर हैं और स्थिति 1971 के बाद सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती है। हालात और बिगड़े तो भारत के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। चिंता युद्ध की या बांग्लादेश से टकराव की नहीं है, बल्कि चिंता यह है कि चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश में पांव पसार लेंगे।

चुनाव से पहले बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले और तेज हो सकते हैं। भारत की पूर्वी सीमा पर एक जेहादी देश का उभरना भारत के लिए खतरे की घंटी बन जाएगा। बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो चुका है। अर्थव्यवस्था और रोजगार के हालात बुरे हैं। सामाजिक अस्थिरता बढ़ रही है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। बांग्लादेश का भविष्य सुरक्षित नहीं लगता।

अरावली पर्वतमाला भारतीय उपमहाद्वीप की पर्यावरणीय रीढ़, जलवायु संतुलन का आधार और रेगिस्तान को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है

अरावली पर्वतमाला विवाद को खनन बनाम पर्यावरण की सरल बहस में सीमित करना गलत होगा, इस मुद्दे पर केवल सोशल मीडिया के नारों पर नहीं बल्कि तथ्यों विज्ञान और कानून के आधार पर संवाद हो- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

अरावली पर्वतमाला विवाद- खनन संरक्षण और सुप्रीम कोर्ट के नए नियमों का समग्र अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण

वैश्विक स्तर पर अरावली पर्वतमाला केवल भारत की एक भौगोलिक संरचना नहीं है,बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप की पर्यावरणीय रीढ़,जलवायुसंतुलन का आधार और रेगिस्तान को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है। लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी यह पर्वतमाला मानव सभ्यता से भी कहीं अधिक प्राचीन है। किंतु विडंबना यह है कि आधुनिक विकास,खनन,शहरीकरण और नीतिगत अस्पष्टताओं के चलते आज यही पर्वतमाला अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। हाल ही में खनन से जुड़े नए नियमों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर सोशल मीडिया पर ए सेव अरावली जैसे हैशटैग ट्रेंड करा, जा रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये नियम अरावली को बचाने के बजाय उसे कमजोर करेंगे। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि इस पृष्ठभूमि में यह आवश्यक हो जाता है कि पूरे विवाद का तथ्यात्मक, कानूनी वैज्ञानिक और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोशल प्रिंट इलेक्ट्रिक मीडिया पर चल रहे विचारों के आदान- प्रदान व डिबेट का समग्र विश्लेषण किया जाए, जो मीडिया में आ रही जानकारी के आधार पर है। साथियों बात कर हम अरावली पर्वतमाला, भौगोलिक विस्तार और ऐतिहासिक महत्व को समझने की करें तो अरावली पर्वतमाला भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात, राजस्थान,हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,47,000 वर्ग किलोमीटर है।यह पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है।अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर (1722 मीटर) माउंट आबू में स्थित है। यह पर्वतमाला थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है और उत्तर भारत के भूजल स्तर,मानसून पैटर्न और जैव विविधता को संतुलित रखने में निर्णायक भूमिका निभाती है।इतिहास की दृष्टि से अरावली ने हड़प्पा सभ्यता, राजपूत राज्यों और मुगल काल में भी जल स्रोतों, खनिजों और प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया।अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक मानकों के अनुसार इतनी प्राचीन पर्वतमालाएं पृथ्वी पर बहुत कम बची हैं, इसलिए अरावली का संरक्षण केवल भारत नहीं बल्कि वैश्विक पर्यावरणीय जिम्मेदारी भी है।खनिज संपदा और खनन का आकर्षणअरावली पर्वतमाला खनिज संसाधनों से भरपूर है।यहां तांबा, जिंक, लेड, ग्रेनाइट, मार्बल और क्वॉर्ट्ज जैसे मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं। औद्योगिक विकास और निर्माण क्षेत्र की बढ़ती मांग ने अरावली को खनन उद्योग के लिए अत्यंत आकर्षक बना दिया। विशेषकर राजस्थान और हरियाणा में दशकों तक अनियंत्रित और अवैध खनन हुआ, जिससे पहाड़ों का क्षरण, जंगलों का विनाश और जल स्रोतों का सूखना शुरू हो गया। यही वह बिंदु है जहां विकास और संरक्षण के बीच टकराव पैदा होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यही बहस अमेजन, एंडीज और अफ्रीको रिफ्ट वैली में देखी गई है। साथियों बात अगर हम चार राज्यों, चार अलग- अलग नियम,भ्रम और पारदर्शिता का संकट इसको समझने की करें तो, अरावली पर्वतमाला चार राज्यों में फैली होने के कारण हर राज्य के अपने-अपने खनन और पर्यावरणीय नियम थे। कहीं पहाड़ियों की परिभाषा अलग थी, कहीं ऊंचाई की सीमा नहीं थी, तो कहीं वन क्षेत्र की पहचान अस्पष्ट थी। इस असमानता के कारण न केवलप्रशासनिक भ्रम पैदा हुआ बल्कि खनन माफिया ने भी इसी अस्पष्टता का लाभ उठाया।अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण शासन (इंवायरमेन्टल गवर्नेंस) के सिद्धांतों के अनुसार, साझा प्राकृतिक संसाधनों के लिए एकरूप नियमों की आवश्यकता होती है। इसी सिद्धांत के तहत अरावली के लिए भी एक समान नीति की मांग लंबे समय से उठ रही थी। साथियों बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप- न्यायपालिका की निर्णायक भूमिका इसको समझने की करें तो, पर्यावरण संरक्षण के मामलों में भारतीय सुप्रीम कोर्ट की भूमिका वैश्विक स्तर पर सराही जाती है। गंगा, यमुना, ताज ट्रेपेजियम और वनों के संरक्षण में कोर्ट के हस्तक्षेप मिसाल रहे हैं। अरावली के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीरता को समझते हुए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया।इस समिति में पर्यावरण मंत्रालय, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया,चारों राज्यों के वन विभाग के अधिकारी और स्वयं सुप्रीम कोर्ट के प्रतिनिधि शामिल थे। यह संरचना अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण आयोगों के अनुरूप थी, जहां नीति, विज्ञान और न्याय का सटीक समन्वय होता है। समिति की सिफारिशें और नवंबर 2025 की मंजूरी-समिति ने विस्तृत सर्वेक्षण,उपग्रह चित्रों, भूवैज्ञानिक डेटा और पर्यावरणीय प्रभावआकलन के आधार पर अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट को सौंपी।नवंबर 2025 में कोर्ट ने इन सिफारिशों को मंजूरी दी। यही वे सिफारिशें है जो आज विवाद का केंद्र बनी हुई है। पहली सिफारिश,100 मीटर ऊंचाई की परिभाषा-नई व्यवस्था के अनुसार, सिर्फ 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला का हिस्सा माना जाएगा।ऐसे क्षेत्रों में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।आलोचकों का कहना है कियससे 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को खनन के लिए खोल दिया जाएगा।किंतु समिति का तर्क है कि वैज्ञानिक रूप से पर्वतमाला की पहचान ऊंचाई, निरंतरता और भूगर्भीय संरचना से होती है।अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक मानकों में भी पर्वत और पहाड़ी के बीच यही अंतर किया जाता है।दूसरी सिफारिश,500 मीटर निरंतरता का सिद्धांत-दूसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि यदि 100 मीटर से ऊंची दो पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर से कम है, तो उस पूरे क्षेत्र को अरावली पर्वत श्रृंखला माना जाएगा और वहां खनन नहीं होगा।यहनियम पर्वतमाला की भौगोलिक निरंतरता को बचाने के लिए है, ताकि खनन के कारण पहाड़ टुकड़ों में न टूट जाएं।यह सिद्धांत यूरोपियन अल्प्स और अमेरिकी अप्लाचियन पर्वतमालाओं में भी अपनाया जाता है।सरकार का पक्ष-90 प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इन नियमों के लागू होने से अरावली का करीब 90 प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित हो जाएगा। खनन केवल 0.19 प्रतिशत क्षेत्र,यानी लगभग 278 वर्ग किलोमीटर में ही संभव होगा। सरकार का दावा है कि इससे अवैध खनन रुकेगा, नियमों में स्पष्टता आएगी और पर्यावरणीय निगरानी बेहतर होगी। साथियों बात कर हम सोशल मीडिया बनाम तथ्य- ए सेव अरावली विवाद इसको समझने की करें तो, सोशल मीडिया पर चल रहे अभियानों में भावनात्मक अपील अधिक और तथ्य कम दिखाई देते हैं। कई पोस्ट्स में यह दावा किया गया कि अरावली को कानूनी रूप से खत्म किया जा रहा है,जबकि वास्तविकता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश संरक्षण को कानूनी मजबूती प्रदान करते हैं।यह प्रवृत्ति वैश्विक स्तर पर भी देखी जाती है, जहां जटिल पर्यावरणीय नीतियों को सरल नारों में प्रस्तुत कर भ्रम फैलाया जाता है।

साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय तुलना,भारत की नीति कहां खड़ी है इसको समझने की करें तो,यदि हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली जैसे देशों से तुलना करें, तो वहां खनन की अनुमति केवल सीमित नियंत्रित और वैज्ञानिक रूप से परिभाषित क्षेत्रों में दी जाती है। भारत में अरावली के लिए बनाए गए नए नियम इसी वैश्विकमानक के अनुरूप हैं। वास्तविक चुनौती,नियम नहीं,उनका क्रियान्वयन अरावली संकट की जड़ केवल नियमों में नहीं,बल्कि उनके ईमानदार क्रियान्वयन में है।यदिस्थानीय प्रशासन, पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया और निगरानी तंत्र मजबूत नहीं हुए, तो सबसे अच्छे नियम भी निष्प्रभावी हो सकते हैं। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि संरक्षण बनाम भ्रम,अरावली पर्वतमाला विवाद को केवल खनन बनाम पर्यावरण की सरल बहस में सीमित करना गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट के नए नियम, यदि सही संदर्भ में देखें, तो वे अरावली को बचाने का एक ठोस कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। आवश्यकता है कि इस मुद्दे पर तथ्य, विज्ञान और कानून के आधार पर संवाद हो, न कि केवल सोशल मीडिया के नारों पर।अरावली का संरक्षण केवल आज की पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि आने वाली

एफटीए : ट्रम्प को ठेंगा

भारत एक के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) कर रहा है। पिछले हफ्ते ओमान के साथ एफटीए किया गया और अब न्यूजीलैंड के साथ बातचीत के बाद एफटीए पर सहमति बन गई है। ?दिसम्बर 2025 तक भारत में अलग-अलग देशों और क्षेत्रीय ब्लाकों के साथ 18 ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। अमेरिका के साथ भारत की व्यापार वार्ता पूरी होने में अभी और कितना वक्त लगेगा इसके बारे में फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता पूरा होने में देरी हो रही है। दोनों देशों के बीच तनाव साफ दिखाई दे रहा है। भारत की इस वक्त मुख्य चुनौती निर्यात के उन क्षेत्रों को नया व्यापार दिलाने की है जो अमेरिकी टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। भारत को नए बाजार भी मिल रहे हैं। भारत में अमेरिका की परवाह किए ?बिना दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड समझौते किए हैं। जिनमें ?ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, मारिशियस, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका और थाइलैंड इत्यादि शामिल हैं। जबकि यूरोपीय यूनियन इजराइल और कनाडा के साथ एफटीए को लेकर बातचीत जारी है। 1990 के दशक में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र स्थापित करने होंगे। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का उदय दमदार शक्तियों के रूप में हुआ। भारत ने 13 अगस्त, 2009 को बैंकाक में भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तब से ही ऐसे समझौतों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुक्त व्यापार समझौता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक देश एक-दूसरे के लिए अपने बाजारों को खोलने के लिए प्रतिबद्ध होते है, जिसमें शुल्क, कोटा या अन्य व्यापार बाधाओं को कम करना या हटाना शामिल है जिससे वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन आसान हो जाता है। मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद के बिल्कुल विपरीत है। मुक्त व्यापार दो मॉडलों पर आधारित होते हैं। पहला व्यापारवाद और दूसरा तुलनात्मक लाभ। भारत इस समय अमेरिकी टैरिफ से हो रहे कारोबार में नुकसान की भरपाई करने में जुटा हुआ है। ओमान के साथ पिछले वित्त वर्ष में भारत का कुल कारोबार 10.6 मिलियन डॉलर था। अब दोनों देशों में एफटीए हो जाने के बाद दोनों देशों का व्यापार और बढ़ेगा। ओमान को निर्यात की जाने वाली भारत की 99 प्रतिशत वस्तुएं शुल्क मुक्त हो जाएंगी और इसकी एवज में ओमान से आयात किए जाने वाले उत्पादों को भी शुल्क मुक्त किया जाएगा। भारत को उम्मीद है कि ऐसे समझौतों से भारत का सेवा क्षेत्र अपनी पैठ बना सकेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को फोन घुमाया और बातचीत के बाद दोनों ने ही एफटीए पर वार्ता सम्पन्न होने की घोषणा की।?इस समझौते से भारत को बहुत फायदा मिलने की उम्मीद है। एफटीए के तहत दोनों देशों के बीच बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी।

इससे व्यापार में बढ़ोतरी, निवेश प्रवाह में इजाफा और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूती मिलेगी। यह समझौता खासतौर पर नवाचार से जुड़े लोगों, उद्यमियों, किसानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), छात्रों और युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगा। कृषि, शिक्षा, तकनीक, स्टार्टअप, सेवाएं और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस मजबूत आधार के साथ भरोसा जताया कि अगले पांच वर्षों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना किया जा सकता है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की ओर से अगले 15 वर्षों में भारत में करीब 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की संभावना भी जताई गई। इसे भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और निवेश के लिए अनुकूल माहौल में अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास के रूप में देखा जा रहा है। भारत को एफटीए से उस खजाने की चाबी मिल गई है जिससे वह अमेरिका और चीन की दादागिरि का जवाब दे सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर बहुत आगे ले जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार में बढ़त देखी जा रही है। वित्त वर्ष 2021 में न्यूजीलैंड से भारत का आयात 381.5 मिलियन डॉलर रहा, जबकि भारत का निर्यात 486.2 मिलियन डॉलर रहा। इस क्षेत्र के जानकार अनुमान लगाते है कि आने वाले वर्षों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार में और भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे दोनों देशों को फायदा होगा। रिपोर्ट बताती है कि भारत की ओर से न्यूजीलैंड को सबसे अधिक निर्यातों में पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दवा निर्माण और जैविक उत्पाद, मोटर गाड़ियां और रेडीमेड कपड़े शामिल हैं। वहीं, न्यूजीलैंड की ओर से भारत में आने वाले सामानों में लोहा और स्टील, कच्ची ऊन, डेयरी प्रोडक्ट्स, ताजे फल, कोयला, लकड़ी के प्रोडक्ट्स आदि शामिल हैं। एफटीए होने के बाद अब दोनों देशों के बीच अन्य कई क्षेत्रों में व्यापार बढ़ने की संभावना है। डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर 100 फीसदी टैरिफ यह कहते हुए लगाया कि भारत रूस से तेल की खरीदारी करता है। इससे मिलने वाले पैसों का रूस, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में यूज करता है। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प के साथ अपने व्यक्तिगत रिश्तों को नजरअंदाज करते हुए देशहित में फैसला लिया और यूएस के द्वारा थोपे गए टैरिफ का जवाब देते हुए कई बड़े कदम उठाए हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड को थोड़ा किनारा करते हुए भारत ने कई देशों के साथ अपने व्यापार को मजबूत कर लिया है। इससे भारत का निर्यात अमेरिका में जहां टैरिफ के कारण कम हुआ, वहीं अन्य देशों में काफी बढ़ गया। एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत को गिराने की कोशिश में ट्रम्प खुद के बने गड्ढे में गिरते हुए दिख रहे हैं। ट्रम्प और अमेरिका की परवाह किए बगैर पीएम मोदी ने रूस के साथ तेल की खरीदारी को जारी रखा है।

अटल जी जिन्होंने देश को आकार दिया व पहाड़ों को दी आवाज!

भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी महज एक स्मृतिोत्सव नहीं है। यह राष्ट्रीय आत्मनिरीक्षण का क्षण है। जब देश अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा है, भारत एक ऐसे नेतृत्व की परंपरा पर चिंतन करने के लिए रुकता है जिसने नैतिक साहस को लोकतांत्रिक संयम, दृढ़ता को सहानुभूति और दूरदर्शिता को विनम्रता के साथ जोड़ा। अटल जी उन दुर्लभ राजनेताओं में से एक थे जिनके लिए राजनीति जनसेवा का एक पवित्र माध्यम थी। उनका नेतृत्व दिखावटी नहीं था, बल्कि प्रेरक था। उनका मानना था कि अधिकार विश्वसनीयता से आना चाहिए और शक्ति जवाबदेही पर आधारित होनी चाहिए। एक प्रतिबद्ध विचार के होते हुए भी, उन्होंने कभी भी विचारधारा को संवाद पर हावी नहीं होने दिया। उनके लिए संसदीय लोकतंत्र एक प्रक्रियात्मक दायित्व नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी थी। प्रधानमंत्री के रूप में, अटल जी ने यह सिद्ध किया कि सशक्त नेतृत्व और मानवीय शासन एक साथ चल सकते हैं। उनके कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ रहते हुए वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनके नेतृत्व ने विश्व को दिखाया कि भारत बिना जल्दबाजी किए दृढ़ संकल्पित हो सकता है, और बिना आक्रामक हुए मुखर हो सकता है। उनके विचार में, शक्ति का अर्थ तभी सार्थक होता है जब वह शांति और स्थिरता के लिए सहायक हो। पोखरण परमाणु परीक्षण रणनीतिक दृढ़ संकल्प का प्रतीक थे, जबकि शांति के लिए उनके प्रयासों ने उनकी कुशल राजनेता की भूमिका को दर्शाया। उनका मानना था कि भारत को सशक्त होने के साथ-साथ उत्तरदायी भी होना चाहिए। विकास के प्रति उनका दृष्टिकोण भी उतना ही महत्वपूर्ण था। अटल जी समझते थे कि राष्ट्रीय प्रगति तभी सार्थक होती है जब वह समावेशी हो। अवसंरचना, ग्रामीण संपर्क और दूरसंचार के क्षेत्र में शुरू की गई महत्वपूर्ण पहलों का उद्देश्य केवल संपत्ति निर्माण करना नहीं था, बल्कि लोगों, बाजारों और अवसरों को आपस में जोड़ना था। सड़कों, संपर्क और प्रौद्योगिकी पर उनके जोर ने दूरस्थ क्षेत्रों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में एकीकृत करने में मदद की और भारत के विकास की नींव रखी। नीति और शासन के अलावा, अटल जी का सबसे बड़ा योगदान भारत को एक सभ्यतागत लोकतंत्र के रूप में समझना था। उनका मानना था कि भारत की शक्ति उसकी विविधता, वाद-विवाद करने की क्षमता और एकता खोए बिना मतभेदों को आत्मसात करने की क्षमता में निहित है। उनका राष्ट्रवाद आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन कभी भी बहिष्कारवादी नहीं था, दृढ़ होते हुए भी सहानुभूतिपूर्ण था। उत्तराखंड में हमारे लिए अटल जी की विरासत बेहद व्यक्तिगत और परिवर्तनकारी है। 9 नवंबर, 2000 को उत्तराखंड (तब उत्तरांचल) का शांतिपूर्ण गठन लोगों की लंबे समय से पोषित आकांक्षा की पूर्ति थी। यह महज प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं था; यह राजनीतिक संवेदनशीलता और राष्ट्रीय दूरदर्शिता का कार्य था। अटल जी समझते थे कि भूगोल शासन को आकार देता है, और जनमानस की आकांक्षाओं के लिए एक विशिष्ट प्रशासनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता राज्य बनने के साथ ही समाप्त नहीं हुई।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने [illegible] एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/[illegible])

वर्कशॉपः टीएमयू में स्टुडेंट्स को समझाई एडवांस्ड क्लीनिकल फिजियोथेरेपी प्रैक्टिसेज

मुरादाबाद।

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के फिजियोथेरेपी विभाग की ओर से एड्वांस्ड क्लीनिकल फिजियोथेरेपी प्रैक्टिसेज पर हुई वर्कशॉप में एल्युमिनाई ने स्टुडेंट्स को क्लीनिकल एक्सपोजर प्रदान करने, केस-आधारित सीखने को बढ़ावा देने, उन्नत फिजियोथेरेपी मूल्यांकन तकनीकों का वास्तविक क्लीनिकल अभ्यास कराया। वर्कशॉप में बीपीटी बैच 2017 के पासआउट और मन्नत फिजियोकेयर, गुरूग्राम के फिजियोथैरेपिस्ट डॉ. मखदूम हसन ने आईटी बैंड सिंड्रोम का समग्र मूल्यांकन एवं उन्नत फिजियोथेरेप्यूटिक रणनीति पर बोलते हुए इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम- आईटीबीएस की विस्तृत व्याख्या की। साथ ही उन्होंने आईटीबीएस के कारण, बायोमैकेनिकल कारकों, क्लीनिकल मूल्यांकन तकनीकों और उन्नत फिजियोथेरेप्यूटिक प्रबंधन तरीकों पर गहन चर्चा की। डॉ. हसन ने केस-आधारित उदाहरण और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण से स्टुडेंटस को व्यावहारिक ज्ञान दिया । बीपीटी बैच 2019 की एल्युमिना और मन्नत फिजियोकेयर, गुरूग्राम की फिजियोथैरेपिस्ट डॉ. ऐमन खान ने प्रसवोत्तर महिलाओं में पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शनः क्लीनिकल मूल्यांकन एवम् फिजियोथेरेप्यूटिक हस्तक्षेप पर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने मूल्यांकन उपकरणों, व्यायाम प्रिस्क्रिप्शन और मरीज-विशिष्ट हस्तक्षेप रणनीतियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। उनके क्लीनिकल अनुभवों ने छात्रों को महिला स्वास्थ्य के इस महत्वपूर्ण पहलू की गहन समझ प्रदान की। दोनों सत्रों में इंटरैक्टिव चर्चाएं, क्लीनिकल डेमोंस्ट्रेशन एवम् व्यावहारिक मार्गदर्शन के जरिए स्टुडेंट्स को व्यावहारिक ज्ञान दिया गया । कार्यक्रम में एल्युमिनाई रिलेशन्स सेल के सहायक निदेशक श्री सिद्धार्थ माथुर, फिजियोथेरेपी विभाग की एचओडी प्रो. शिवानी एम. कौल, एल्युमिनाई समन्वयक डॉ. नंद किशोर साह आदि के संग-संग फिजियोथैरेपी के छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

विण्टर वण्डरलैण्ड कार्निवल मे नन्हें-मुन्नों ने की मस्ती

मुरादाबाद।

जी.डी. गोएंका टॉडलर हाउस प्ले स्कूल में विण्टर वण्डरलैण्ड कार्निवल का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में छोटे ब'चों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जी.डी. गोएंका की डायरेक्टर डॉ0 मल्लिका गोयल ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन ढाई साल से दस साल तक के ब'चों के लिए किया गया था। जी.डी. गोएंका स्कूल के बच्चों के साथ-साथ बाहर के अन्य स्कूलों के बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से फोटो बूथ, गेम स्टॉल, बच्चों के झूले, फन एक्टीविटीज, फूड स्टॉल, सरप्राइज गिफ्ट, लकी ड्रॉ. टैटू स्टेशन थे। सनसैट स्कॉलर्स की डायरेक्टर श्रीमती पवनीत गोयल ने बताया कि इस कार्यक्रम में सबसे 'यादा टैटू स्टेशन व फोटो बूथ ने बच्चों का मन मोह लिया। क्योंकि बच्चों के फोटो हाथ के हाथ उन्हें मिल रहे थे. इस प्रकार के प्रोग्राम से बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। गेम स्टॉल में भी ब'चों ने कई तरह के इनाम जीते। लकी ड्रा में तीन विनर रहे। यह कार्यक्रम जी.डी. गोएंका और सनसैट स्कॉलर्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चे, तथा उनके अभिभावक, शहर के गणमान्य लोग व जी.डी. गोएका प्ले स्कूल व सनसैट स्कॉलर्स के सभी शिक्षकगण मौजूद रहे।

ब्रिटेन में बहराइच की बेटी कुमकुम गुप्ता को अंतरराष्ट्रीय गौरव

बहराइच। जिले के लिए गर्व का क्षण है। बहराइच के प्रमुख व्यवसाई कमल शेखर गुप्ता की प्रिय भांजी कुमकुम गुप्ता को ब्रिटेन में प्रतिष्ठित टेक वूमेन 100 अवॉर्ड-2025 से सम्मानित किया गया हैयह सम्मान उन्हें तकनीकी क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं की श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार केपीएमजी (केएमपीजी) के सहयोग से आयोजित अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिया गया, जिसमें विश्वभर से चयनित प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कुमकुम गुप्ता की इस उपलब्धि से न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे बहराइच जनपद में हर्ष और गौरव का वातावरण है। परिजनों, शुभचिंतकों और व्यवसायिक जगत से जुड़े लोगों ने कुमकुम गुप्ता को बधाई देते हुए इसे युवाओं, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया है। उनका यह सम्मान यह दर्शाता है कि मेहनत, प्रतिभा और लगन के बल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई जा सकती है।

डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक

बहराइच।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में सआदत इन्टर कालेज नानपारा में विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें उप जिलाधिकारी नानपारा/उपाध्यक्ष मोनालिसा जौहरी, तहसीलदार/प्रबन्धक रविकान्त द्विवेदी, प्रधानाचार्य अरविन्द कुमार मिश्र, समिति के सदस्य आनन्द कुमार अग्रवाल सहित विद्यालय के शिक्षकगण मौजूद रहे। बैठक के दौरान विद्यालय प्रबन्ध समिति के 02 रिक्त सदस्य पद पर सत्य प्रकाश गुप्ता एव नरेश चन्द्र अग्रवाल के चयन, विद्यालय के अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास एवं अंग्रेजी प्रवक्ता पदों पर सहायक शिक्षकों की पदोन्नति तथा सहकारी बैंक नानपारा में जमा विद्यालय की धनराशि का आहरण कराये जाने पर विचार-विमर्श किया। डीएम ने कहा कि जो सदस्य विद्यालय के विकास में अग्रणी भूमिका निभाना चाहते हैं उन्हें साधारण सभा का सदस्य बनाया जाय। डीएम श्री त्रिपाठी ने कहा कि ऐसे पुरातन छात्र जो विद्यालय के विकास के लिए आकांक्षी हो उन्हें सम्मानपूर्वक आमंत्रित कर सम्मानित किया जाय तथा उन्हीं के हाथों कायाकल्प के कार्यों का लोकार्पण भी कराया जाय। विद्यालय की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी नानपरा को निर्देश दिया गया कि पैमाइश कराकर विद्यालय की भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जाय साथ ही विद्यालय की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण का प्रस्ताव भी तैयार कराया जाय। डीएम ने शिक्षण स्टाफ को निर्देश दिया कि अध्ययनरत छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ उन्हें सामाजिक गतिविधियों के लिए भी प्रेरित किया जाय।

तैयार हुई निर्वाचक नामावली

मुरादाबाद। अपर जिलाधिकारी प्रशासन/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) संगीता गौतम ने जनपद मुरादाबाद की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकगण को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार हो गई है और उसकी एक प्रति संबंधित तहसील के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय और संबंधित खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नामावली का कार्यालय समय में निरीक्षण कर सकता है। यदि नामावली में किसी के सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा अथवा किसी प्रकार के अन्य विवरणों के संबंध में कोई संशोधन अपेक्षित हो अथवा सम्मिलित किसी नाम के संबंध में कोई आपत्ति हो तो उसे ×0 दिसम्बर 2025 को या उससे पूर्व प्रपत्र 2, 3 या 4 में जो भी उपयुक्त हो, दाखिल किया जाये।

भाजपाईयों ने की अटल जी की प्रतिमा की साफ-सफाई

मुरादाबाद। भारतीय जनता पार्टी महानगर के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल एवं महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला के नेतृत्व में भारत रत्न श्रद्धेय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के जन्म शताब्दी वर्ष पर अटल स्मृति वर्ष के अंतर्गत जिला महानगर कार्यालय एवं महानगर के सभी दस मंडलों में अटल घाट कटघर एवं अटल पथ सिविल लाइन पर महानगर के जनप्रतिनिधिगण, महानगर के पदाधिकारीगण मंडल,मोर्चा, प्रकोष्ठों कार्यकर्तागण ने प्रातः 11 बजे अटल जी की प्रतिमा की साफ सफाई कर एवं पुष्प अर्पित कर नमन किया तदोपरान्त शाम 6 बजे महानगर कार्यालय एवं अटल पथ पर मुख्य अतिथि महापौर विनोद अग्रवाल ने अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं उनके समक्ष दीप प्र'ज्वलित कर नमन किया।

कार्यक्रम में महापौर विनोद अग्रवाल ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेई जी के जीवन पर प्रकाश डाला एवं उनके बताए रास्ते पर चलने का आवाहन किया उन्होंने कहा कि अटल जी की राजनीतिक यात्रा एवं उनके शासन में सुशासन का महत्वपूर्ण योगदान रहा जिसमें उनके द्वारा किए गए कार्य बुनियादी ढांचे विदेश नीति और जनकल्याण के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण सुधार शामिल हैं जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल कहा कि हमें अटल जी के राष्ट्र प्रथम मूल्यों के सिद्धांतों पर चलना चाहिए।महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने कहा कि हमें भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई जी की विरासत को विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लिए राष्ट्रव्यापी सहभागिता पूर्ण गतिविधियों का संचालन करके नागरिकों एवं युवाओं को प्रेरित करना है। अटल पथ पर अटल प्रतिमा पर दीप प्र'ज्वलित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापौर विनोद अग्रवाल जिला एवं महानगर कार्यालय पर जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला एवं महानगर महामंत्री नत्थूराम कश्यप दिनेश शोर्षवाल पूर्व महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा कार्यक्रम संयोजक विशाल त्यागी सह संयोजिका सुनीता शर्मा प्रांतीय परिषद सदस्य निमित जायसवाल प्रांतीय परिषद सदस्य संजय छक्का महानगर मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता चकित चौधरी महानगर उपाध्यक्ष नवदीप टंडन राहुल शर्मा दिनेश सिसोदिया हेमराज सैनी चंद्र प्रजापति,शम्मी भटनागर सर्वेश पटेल अभिषेक चौबे कशिश चौहान विजय लक्ष्मी पंडित पंकज शर्मा सुनीता सैनी हेमा खत्री पूर्णिमा खन्ना रुचि चौधरी विपिन प्रजापति विशाल रस्तौगी मिथुन शर्मा सोमपाल प्रजापति राजीव शर्मा वीरपाल सिंह कपिल गुप्ता सूर्य मोहन शमशेरी गजेंद्र लोदी संजय कुमार अनमोल सक्सैना अनूप महरोत्रा विजय वर्मा पिंकू गुप्ता अर्चित गुप्ता सुरदीप सिंह सुमित अग्रवाल हरेंद्र शर्मा विकी कुमार नीरज कुमार विनय राजोरिया महिपाल सिंह आदि महानगर मंडल मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं पार्षदगण शामिल रहे।

सम्प्रेक्षण ग्रह में आयोजित हुआ काव्यांजलि कार्यक्रम

मुरादाबाद।

राजकीय सम्प्रेक्षण ग्रह (किशोर) मुरादाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्मृतिशेष अटल बिहारी वाजपेयी की 101 वीं जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर काव्यांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय सम्प्रेक्षण ग्रह (किशोर) मुरादाबाद के अधीक्षक मुकेश चौधरी ने की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी धवल दीक्षित विशिष्ट अतिथि सम्भल से आये हास्य-व्यंग्य के वरिष्ठ कवि अतुल शर्मा रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्र'ज्वलन के साथ हुआ। सरस्वती वंदना पूजा राणा के द्वारा प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का संचालन कवि ईशांत शर्मा ईशू ने किया। कार्यक्रम में बोलते हुए सम्प्रेक्षण के अधीक्षक मुकेश चौधरी ने कहा कि ऐसे आयोजन किशोर को देश के महान व्यक्तित्व से परिचय कराने व उनके विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है ऐसे कार्यक्रम राजकीय सम्प्रेक्षण ग्रह (किशोर) मुरादाबाद में किशोर के सर्वांगीण विकास के लिए आयोजित किए जाते रहते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए धवल दीक्षित ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को देश की महान विभूतियों एवं शहीदों से परिचित कराना चाहिए, उन्हें मालूम होना चाहिए कि यह आजादी हमें किस प्रकार से अपना सर्वस्व लुटाकर हमारे वीर शहीद ने हमे दी है हमें जीवन में हमेशा अपनी महान विभूतियों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम में अवधेश विद्यार्थी, आवरण अग्रवाल श्रेष्ठ, महावीर सिंह, पूजा राणा, ईशांत शर्मा ईशू, रवि चतुर्वेदी ने स्वरचित रचनाओं और अटल जी की कविताओं से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कविताओं के माध्यम से काव्याजलि समर्पित की गई।

एसबीएस स्कूल में हुआ खेलकूद प्रतियोगिता का समापन

बिलारी।

एसबीएस स्कूल में दिनांक तीन दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता (स्पोर्ट्स मीट) का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। इस खेल महोत्सव का शुभारंभ विद्यालय के डायरेक्टर राजीव सहाय एवं प्रधानाचार्य संयोग वसिष्ठ द्वारा किया गया। खेल महोत्सव के प्रथम दिन विद्यालय के चारों हाउस डायमंड, एमराल्ड, रूबी एवं सैफायर के बीच खो-खो प्रतियोगिता आयोजित की गई । खो-खो (बालक वर्ग) में रूबी हाउस ने प्रथम, एमराल्ड हाउस ने द्वितीय तथा सैफायर हाउस ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। खो-खो (बालिका वर्ग) में डायमंड हाउस ने प्रथम, रूबी हाउस ने द्वितीय एवं सैफायर हाउस ने तृतीय स्थान हासिल किया। द्वितीय दिन विद्यालय में अंतर-हाउस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्रिकेट (बालक वर्ग) में डायमंड हाउस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि रूबी हाउस द्वितीय स्थान पर रहा। क्रिकेट (बालिका वर्ग) में डायमंड हाउस ने प्रथम तथा एमराल्ड हाउस ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मुकाबले अत्यंत रोमांचक रहे। तीसरे एवं अंतिम दिन वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एवं एथलेटिक्स (ट्रैक एंड फील्ड) की प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। वॉलीबॉल (बालक वर्ग) में डायमंड हाउस ने प्रथम, एमराल्ड हाउस ने द्वितीय तथा सैफायर हाउस ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बास्केटबॉल (बालिका वर्ग) में सैफायर हाउस प्रथम, डायमंड हाउस द्वितीय एवं एमराल्ड हाउस तृतीय स्थान पर रहा। एथलेटिक्स में बालक वर्ग में डायमंड हाउस प्रथम एवं रूबी हाउस द्वितीय रहा, जबकि बालिका वर्ग में एमराल्ड हाउस प्रथम एवं रूबी हाउस द्वितीय स्थान पर रही। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में विद्यालय के खेल शिक्षक श्री यशवीर चौधरी, श्री आशीष चौधरी एवं श्री सुमित शर्मा का विशेष योगदान रहा, जिनके कुशल मार्गदर्शन में सभी प्रतियोगिताएँ अनुशासन एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुईं। साथ ही विद्यालय की समन्वयक (कोऑर्डिनेटर) नाज़िया ख़ान की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके सहयोग से संपूर्ण आयोजन सुचारु रूप से सम्पन्न हुआ। समापन अवसर पर डायरेक्टर राजीव सहाय एवं प्रधानाचार्य संयोग वसिष्ठ ने सभी विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ियों को बधाई दी।

26 जनवरी, के लिए दिल्ली को पूरी तरह से किया जा रहा तैयार, सीएपीएफ की की 53 कंपनियां की जाएगी तैनात

नई दिल्ली। 26 जनवरी, 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह से पहले, गृह मंत्रालय ने बढ़ी हुई सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 53 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। 5,800 से अधिक सशस्त्र कर्मियों वाली ये अतिरिक्त बल मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तैनात की जाएंगी, जबकि दिल्ली पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नोडल एजेंसी बनी रहेगी। अतिरिक्त सीएपीएफ कर्मियों को कर्तव्य पथ के दो किलोमीटर के दायरे में सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया जाएगा - यह लगभग 3 किलोमीटर लंबा औपचारिक मार्ग है जो रायसीना हिल पर स्थित राष्ट्रपति भवन (राष्ट्रपति का निवास) से इंडिया गेट तक जाता है, जहां हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आयोजन होता है। यह तैनाती वार्षिक परेड की तैयारी और समापन के दौरान पूरे क्षेत्र पर व्यापक नियंत्रण सुनिश्चित करेगी। ये बल गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों, मार्गों और स्थलों पर सुरक्षा बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की सहायता करेंगे। इन बलों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवान शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सहायक इकाइयों सहित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की टीमें शहर के रणनीतिक स्थानों, ऊंची इमारतों और अन्य संवेदनशील स्थलों पर तैनात की जाएंगी। सुरक्षा के ये कड़े उपाय भारत सरकार के उस निर्णय के बाद किए गए हैं जिसमें उसने गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व को संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इस कदम को भारत की ओर से एक महत्वपूर्ण राजनयिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इन दोनों नेताओं के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परेड में शामिल होने की उम्मीद है। उनकी यात्रा संभवतः भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के साथ मेल खाएगी, जिसके दौरान दोनों पक्षों द्वारा लंबे समय से लंबित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस वर्ष अतिरिक्त एहतियाती उपाय अपनाए हैं, विशेष रूप से 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए बम विस्फोट के मद्देनजर, जब एक आत्मघाती हमलावर ने चलती हुई हुंडई आई20 कार के अंदर विस्फोटक उपकरण में विस्फोट कर दिया था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। हमलावर की पहचान बाद में उमर-उन-नबी के रूप में हुई। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों के आसपास बढ़े हुए खतरे की आशंका जताने वाली नई खुफिया जानकारी के बाद अतिरिक्त सीएपीएफ (कैपिटल सिक्योरिटी फोर्स) की तैनाती को मंजूरी दे दी है। दिल्ली पुलिस के निर्देशानुसार, नए दल बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचे के तहत संवेदनशील स्थानों पर पहले से तैनात बलों के साथ एकीकृत किए जाएंगे।

कुलदीप सिंह सेंगर की बेल पर भड़के राहुल, कहा- हम एक 'मृत समाज' बनते जा रहे हैं

नई दिल्ली । 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के बाद, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे निराशाजनक और शर्मनाक बताया और पीड़िता के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर सवाल उठाए। उन्होंने आगे दावा किया कि भारत न केवल एक मृत अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है, बल्कि ऐसी अमानवीय घटनाओं के कारण एक मृत समाज भी बनता जा रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, क्या सामूहिक बलात्कार पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या न्याय के लिए आवाज उठाने का साहस दिखाना उसकी गलती है? उसके अपराधी (पूर्व भाजपा विधायक) को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार-बार परेशान किया जा रहा है और वह डर के साये में जी रही है। गांधी ने चेतावनी देते हुए कहा, बलात्कारियों को जमानत और पीड़ितों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार - यह किस तरह का न्याय है? उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आगे टिप्पणी की कि इस तरह की घटनाएं न केवल संस्थागत विफलता बल्कि गहरे नैतिक पतन का संकेत देती हैं। एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि हम न केवल एक मृत अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं, बल्कि ऐसी अमानवीय घटनाओं के कारण हम एक मृत समाज में भी तब्दील होते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना एक अधिकार है, और उसे दबाना एक अपराध है। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए - न कि बेबसी, भय और अन्याय। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि जब उन्हें और उनकी दो बेटियों को सीआरपीएफ के वाहन में ले जाया जा रहा था, तो उन्हें अचानक सड़क किनारे उतार दिया गया और सुरक्षा गार्ड उनकी बेटियों को अपने साथ ले गए। उन्होंने आगे आरोप लगाया, हमें न्याय नहीं मिला... वे मेरी बेटी को भी बंधक बनाकर ले जा रहे हैं... वे मेरी बेटी को मारना चाहते हैं... वे मेरी बेटियों को सीआरपीएफ के वाहन में ले गए... कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द होनी चाहिए; अन्यथा हम अपनी जान दे देंगे... अन्यथा हमें मार दिया जाएगा, हम सुरक्षित नहीं हैं। एक दिन पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत (सजा का निलंबन) दे दी थी। उन्हें दिल्ली की पोक्सो अदालत ने एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया था और वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने उनकी अपील लंबित रहने तक सजा को निलंबित कर दिया।

पूरे पंजाब में पुतले फूंकने की तैयारी

29 को केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे किसान

पंजाब । किसान मजदूर मोर्चा भारत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) में मोदी सरकार द्वारा किए गए हालिया विवादित परिवर्तनों की कड़ी आलोचना की है। उनका आरोप है कि नई नीतियों का उद्देश्य देशभर में एमजीएनआरईजीए श्रमिकों को रोजगार से वंचित करना है। मोर्चे का तर्क है कि ठेकेदारी कार्यालयों और पंचायतों से कार्यान्वयन शक्तियां छीनकर केंद्र सरकार कार्य अनुमोदन पर अपना नियंत्रण केंद्रीकृत कर रही है। इस बदलाव का विरोध करने के लिए वे इस महीने के अंत से शुरू होने वाले जिला स्तरीय प्रदर्शनों की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। संगठन ने कहा कि केंद्र सरकार ने एमजीएनआरईजीए के लिए धनराशि में लगभग 40 प्रतिशत की कटौती करके इसे प्रभावी रूप से सीमित करने का निर्णय लिया है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायतों और राज्य सरकार के संस्थानों-विशेष रूप से ठेकेदारी कार्यालयों, जिन्होंने एमजीएनआरईजीए कार्यों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी-को प्राप्त अधिकार छीने जा रहे हैं। मोर्चे के अनुसार, केंद्र सरकार अब यह निर्णय केंद्रीकृत कर रही है कि किन कार्यों को मंजूरी दी जाएगी और किसे रोजगार दिया जाएगा, जिससे स्थानीय स्वशासन कमजोर हो रहा है। मोर्चे ने यह भी दावा किया कि एमजीएनआरईजीए के तहत अनुमत कार्यों की कई श्रेणियों में कटौती की जा रही है। अकेले पंजाब में ही लगभग 11-12 लाख जॉब कार्ड हैं, जबकि पूरे भारत में लगभग 12 करोड़ श्रमिक अपनी आजीविका के लिए एमजीएनआरईजीए पर निर्भर हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि इन श्रमिकों को बेरोजगारी की ओर धकेलकर केंद्र सरकार कॉरपोरेट घरानों को सस्ता श्रम उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। इन नीतियों के विरोध में, किसान मजदूर मोर्चा भारत ने घोषणा की है कि वह 29 दिसंबर को पंजाब के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर मोदी सरकार का पुतला जलाएगा। मोर्चे ने मांग की कि एमजीएनआरईजीए को उसके पूर्व स्वरूप में बहाल और लागू किया जाए। इसने गारंटीकृत कार्य को बढ़ाकर 200 दिन प्रति वर्ष करने और दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 700 रुपये करने की भी मांग की। इसके अतिरिक्त, संगठन ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार श्रम कानूनों का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि ये कानून देशभर में श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। मोर्चे ने यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त किया कि श्रमिकों और मजदूरों के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा होने तक संघर्ष जारी रहेगा। इससे पहले, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन ने केंद्र में विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (जी-राम जी) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में द्रमुक और उसके सहयोगियों के नेताओं ने भाग लिया, जिन्होंने इस कदम को एमजीएनआरईजीए से महात्मा गांधी की विरासत को मिटाने का प्रयास बताया।

रूस-यूक्रेन शांति वार्ता जैसा गठबंधन,

फडणवीस का शिवसेना-मनसे पर तीखा वार

मुंबई । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को शिवसेना (यूबीटी)-महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) गठबंधन को खारिज करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होने के बावजूद अपने गठबंधन को लेकर कृत्रिम प्रचार करने की कोशिश कर रही है।

पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि इस गठबंधन को ऐतिहासिक घटना के रूप में पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा, वे इस तरह का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता जैसी कोई ऐतिहासिक घटना घट रही हो, जिसमें राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अंततः आमने-सामने बैठे हों। यह प्रचार शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस दोनों द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियों ने तुष्टिकरण की राजनीति के जरिए खुद को कमजोर कर लिया है, जिससे उनके वोट बैंक में लगातार गिरावट आ रही है। फडणवीस ने कहा कि ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति में लिप्त होकर और अपना समर्थन खोकर अपनी प्रासंगिकता खो दी है। इनके गठबंधन से जनता को कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने आगे दावा किया कि यह गठबंधन विचारधारा से प्रेरित नहीं बल्कि राजनीतिक हताशा से प्रेरित है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि अपने अस्तित्व को बचाने के हताश प्रयास में, उन्होंने हाथ मिला लिया है, यह मानते हुए कि कोई भी पार्टी अकेले नहीं जीत सकती। हालांकि, महाराष्ट्र की जनता ने हमारा काम देखा है, और इसी आधार पर महायुति विजयी होगी। इससे पहले, ठाकरे भाई राज और उद्धव पहले बालासाहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने और फिर जनवरी में होने वाले आगामी बीएमसी चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा करने के लिए एक साथ आए।

बीएमसी चुनाव साथ में लड़ेंगे उद्धव और राज ठाकरे, गठबंधन का किया ऐलान

मुंबई । राज ठाकरे द्वारा अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे से मतभेदों के बाद अविभाजित शिवसेना छोड़ने और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन करने के बीस साल बाद, दोनों चचेरे भाइयों ने बुधवार को 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा की। ठाकरे भाइयों ने कहा कि उनकी पार्टियों के बीच सीटों के औपचारिक बंटवारे की घोषणा जल्द ही की जाएगी। जब नेता अपने परिवारों के साथ मंच पर आए, तो शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने इस क्षण को एक शुभ शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन बीएमसी और अन्य नगर निगमों पर भगवा झंडा लहराते रहने की सकारात्मक शुरुआत है और यह केवल ठाकरे बंधुओं के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। अपने चचेरे भाई के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने इस महत्वपूर्ण घोषणा के संबंध में कहा कि वे अब हमेशा एकजुट रहने के लिए एक साथ आए हैं और मराठी मानुष को सशक्त बनाना उनके लिए सर्वोपरि है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कुछ ताकतों पर मुंबई को नष्टकरने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि लगातार आपसी कलह हुतात्मा का अपमान होगा और उन्होंने जोर देकर कहा कि मुंबई को मराठी मानुष से कभी नहीं छीना जा सकता। भाजपा के नारे बटेंगे तो कटेंगेका जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने मराठी मानुष से एकजुट रहने का आह्वान किया और चेतावनी दी कि अब लड़खड़ाने से विभाजन होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे ठाकरे बंधुओंके रूप में एक साथ आए हैं। उन्होंने अपने दादा प्रबोधनकर ठाकरे की विरासत को याद किया, जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया था, और कहा कि मुंबई के राज्य का हिस्सा बनने के बाद, शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने पार्टी की स्थापना की। उन्होंने बताया कि शिवसेना को अपनी स्थापना के बाद से 60 साल हो चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र किसी भी आपसी मतभेद से बड़ा है। हम यह घोषणा करते हैं कि हमारा गठबंधन बन चुका है और मुंबई का मेयर मराठी होगा और हमारा होगा। महाराष्ट्र जिस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि शिवसेना और मनसे एक साथ आएं, आज हम उसकी आधिकारिक घोषणा कर रहे हैं।

मुझे दिल्ली में होती है एलर्जी...,

दिल्ली की जहरीली हवा से चिंतित नितिन गडकरी, बोले- 40फीसदी प्रदूषण ट्रांसपोर्ट से

नई दिल्ली । दिल्ली में व्याप्त भीषण प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकार किया कि प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र का योगदान लगभग 40 प्रतिशत है। उदय माहूरकर द्वारा लिखित पुस्तक माई आईडिया ऑफ नेशन फर्स्ट - रिडिफाइनिंग अनएलॉयड नेशनलिज्म के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए गडकरी ने कहा कि प्रदूषित हवा के कारण राष्ट्रीय राजधानी में दो दिन रहने के बाद ही उन्हें संक्रमण हो जाता है। गडकरी ने कहा कि यदि आज के समय में कोई सच्चा राष्ट्रवाद है, तो वह आयात कम करने और निर्यात बढ़ाने में निहित है। मैं दिल्ली में सिर्फ दो दिन रहता हूं और मुझे संक्रमण हो जाता है। दिल्ली प्रदूषण से इतना पीड़ित क्यों है? गडकरी ने स्वीकार किया, मैं परिवहन मंत्री हूं, और 40फीसदी प्रदूषण हमारे कारण होता है।परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जीवाश्म ईंधन के आयात पर सालाना 22 लाख करोड़ रुपये खर्च करने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए वैकल्पिक और जैव ईंधन में अधिक आत्मनिर्भरता की अपील की। उन्होंने पूछा कि हम जीवाश्म ईंधन के आयात पर 22 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। यह किस तरह का राष्ट्रवाद है? इतना पैसा खर्च करके हम अपने ही देश को प्रदूषित कर रहे हैं। क्या हम वैकल्पिक ईंधन और जैव ईंधन में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते? इस बीच, बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में जहरीली धुंध की मोटी परत छा गई, आईटीओ क्षेत्र से तस्वीरें सामने आईं और वायु गुणवत्ता और भी खराब हो गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी चरण-IV के तहत सभी कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, आईटीओ क्षेत्र के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 374 दर्ज किया गया, जिसे अत्यंत खराब श्रेणी में रखा गया है। विपक्ष ने संसद में प्रदूषण पर चर्चा की मांग की थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी तक, सभी नेताओं ने सरकार से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ देना हमारे लिए पाप है

लखनऊ ।

यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के दिए गए सुझाव के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने तंज भी कसा। नेता सदन सीएम योगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो भी सुझाव हमारी सरकार को दिए हैं अगर वो सत्ता में रहने पर सपा नेताओं को देते तो समाजवादी पार्टी तितर-बितर न होती। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम हर किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। किसी का नाम और चेहरा देखकर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दे रहे हैं। ये हमारे लिए पाप है। विकास योजनाओं का लाभ हर किसी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि नेता प्रतिपक्ष ने स्वीकार किया कि प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज प्रदेश की पहचान बदली है। अब प्रदेश में सुरक्षा का एक माहौल है। सपा की ही सरकार थी लेकिन पूजा पाल को सपा की सरकार न्याय नहीं दिला सकी क्योंकि हिम्मत नहीं थी। हमारी सरकार ने तय किया कि बेटी चाहे इस पक्ष की हो या विपक्ष की उसे न्याय हम देंगे। सरकार की प्राथमिकता में है कि प्रदेश की हर बेटी को, हर व्यापारी को, हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कहीं भी

किसी को जबरन कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। अगर किसी ने कब्जा किया है तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि हमने योजनाओं में जो लूट थी उसे रोका। सपा के लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। बड़े-बड़े दावे करते हैं। जेपीएनआईसी पौने दो सौ करोड़ का प्रोजेक्ट था 860 करोड़ खर्च हो जाने के बाद भी अधूरा है। गोमती रिवर फ्रंट 167 करोड़ का प्रोजेक्ट था 1400 करोड़ खर्च हो गए तब भी अधूरा है।

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सिविल वर्क के लिए 15 हजार 200 करोड़ रुपये तय किए गए थे हमने वही एक्सप्रेस वे 11 हजार 400 करोड़ रुपये में पूरा करके दिखा दिया। यही सपा के समय इंफ्रास्ट्रक्चर की सच्चाई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमने कानून व्यवस्था में सुधार किया है। यही कारण है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। आज निवेशक प्रदेश में आने के लिए तैयार है। प्रदेश में अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। हमें खुशी है कि हमने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्यों की सूची से बाहर निकाला है।

आज प्रदेश में व्यापारियों से गुंडा टैक्स नहीं लिया जाता है। आज अगर कोई गुंडा किसी बेटी को छेड़ता है तो वो जानता है कि जल्द ही यमराज का बुलावा आ जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जितना सपा ने किया उतना किसी ने नहीं किया। हमने नौ लाख सरकारी नौकरियां दी है लेकिन कहीं भी पक्षपात नहीं हुआ है। सपा की सरकार में यूपी के लोगों के सामने पहचान का संकट था। लोगों में अपने जीवन के लिए भय था अब प्रदेश की पहचान बदली है। आज देश में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे और एयरपोर्ट वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। हमने भर्तियों को पारदर्शी बनाया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमने भर्ती बोर्ड में रिटायर्ड डीजीपी को बैठाया है। जिससे कि नकल माफियाओं की कमर तोड़ी जा सके। सज्जन को सुरक्षा और दुर्जन को ठिकाने लगाने के लिए ही तो हम बैठे हैं। कोई भजन करने के लिए तो बैठे नहीं हैं। भजन करने के लिए तो मठ ही पर्याप्त है। उसी में कर लेते। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्... इसीलिए तो हम आए हैं। यही हमारी शपथ है।

बैतूल के बोरदेही घाट में पलटी पिकअप, 31 ग्रामीण घायल

बैतूल । मध्यप्रदेश के बैतूल जिलांतर्गत आने वाले खेड़ली बाजार-बोरदेही मार्ग पर ग्राम दूरा बोरगांव के पास घाट क्षेत्र में एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में वाहन में सवार 31 ग्रामीण घायल हो गए। सभी लोग छिंदवाड़ा जिले के ग्राम सेमरिया से मुलताई में आयोजित दसवां कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही तीन एंबुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को मुलताई के शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। अस्पताल के बीएमओ प्रवीण मीणा ने बताया कि अधिकांश घायलों को मामूली व अंदरूनी चोटें आई हैं और सभी की हालत फिलहाल स्थिर है। घायलों के अनुसार सामने अचानक आए एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के प्रयास में पिकअप चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे वाहन पलट गया। घायलों में सेमरिया के अलावा उमेरठेल और चोपना क्षेत्र के ग्रामीण भी शामिल हैं। हादसे में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी घायल हुए हैं। इस घटना ने एक बार फिर मालवाहक वाहनों में सवारी ले जाने की गंभीर समस्या को उजागर कर दिया है।

पीएम मोदी आज लखनऊ में करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण

लखनऊ ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को एक दिन के दौरे पर लखनऊ में रहेंगे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बसंतकुंज में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन पर लखनऊ में विभिन्न मार्गों पर यातायात डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) यातायात कमलेश दीक्षित ने बताया कि बुधवार रात 11 बजे से व्यवस्था लागू होगी और गुरुवार को कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे में वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें। इस दौरान ट्रैफिक समस्या आने पर कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह व्यवस्था रहेगी लागू

मलिहाबाद चौराहे से बाजनगर किसान पथ/इन्दौरिया की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे। वाहन जीरो प्वाइंट मोहान रोड होकर जा सकेंगे।

मुजासा तिराहे से बाजनगर किसानपथ/इन्दौरिया की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे, बल्कि जीरो प्वाइंट मोहान रोड होकर जा सकेंगे।

- प्रधानमंत्री के गुरुवार शाम को प्रस्थान के बाद तक जारी रहेगा यातायात में बदलाव
- लखनऊ के साथ पड़ोसी जिलों के लोग भी लें यातायात व्यवस्था में बदलाव का संज्ञान

पड़ोसी जिलों की पुलिस भी रहेगी अलर्ट, वैकल्पिक मार्गों का करें प्रयोग

बाजनगर किसान पथ अंडरपास से इन्दौरिया बाईपास तिराहा की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगेय यह किसानपथ होकर जा सकेंगे। कसमण्डी (हमसफर लान) अंडरपास से अंधे की चौकी तिराहा की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे, बल्कि किसानपथ होते हुए जा सकेंगे।

इन्दौरिया बाईपास तिराहा से कार्यक्रम स्थल/भिठौली तिराहा की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे, बल्कि अंधे की चौकी तिराहा, बाजनगर किसानपथ अंडरपास से किसानपथ या दुबग्गा तिराहा होकर जा सकेंगे। तिकोनिया तिराहा से दुबग्गा तिराहा/इन्दौरिया बाईपास तिराहा की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे, बल्कि नहर तिराहा मोहान रोड, खुशहालगंज बाजार होते हुए खुशहालगंज किसानपथ अंडरपास से किसानपथ होकर जा सकेंगे।

भिठौली तिराहे से कार्यक्रम स्थल/इन्दौरिया बाईपास तिराहा की तरफ भारी/बड़े/कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे, बल्कि सैरपुर तिराहा, अस्ति क्रासिंग, बख्शी तालाब होते हुए इंदौराबाग किसानपथ अंडरपास से किसानपथ या इंजीनियरिंग कालेज चौराहा होकर जा सकेंगे।

नया पक्कापुल तिराहा/कुड़ियाघाट तिराहा से कार्यक्रम स्थल/पैला तिराहा की तरफ बड़े/कामर्शियल वाहन नहीं जा सकेंगे, बल्कि रूमीगेट, कोनेश्वर चौराहा, बालागंज चौराहा, दुबग्गा तिराहा होकर जा सकेंगे। दुबग्गा तिराहे से कोई भी वाहन इन्दौरिया या सीतापुर बाईपास की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि तिकोनिया तिराहा होते हुए जा सकेंगे। नहर पुल तिराहे से कोई भी वाहन बुद्धेश्वर की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि जीरो प्वाइंट या किसान पथ के ऊपर से होकर जा सकेंगे।